मेन्स मास्टर

भारत की बढ़ती पड़ोस संबंधी दुविधाएँ

I. **पृष्ठभूमि:**
• भारतीय विदेश नीति का लक्ष्य वैश्विक नेतृत्व है लेकिन उसे अपने पड़ोस में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
• दक्षिण एशिया में अनोखी दुविधाएं हैं, जिनमें भारत विरोधी शासन और चीन का बढ़ता प्रभाव शामिल है।
द्वितीय· भारत द्वारा सामना की जाने वाली दुविधाएँ:
राजनीतिक चुनौतियाँ:
• राजनीतिक रूप से भारत विरोधी शासन का उदय, जैसा कि मालदीव में देखा गया।
• संभावित वैचारिक चुनौतियाँ, जैसे ढाका में खालिदा जिया के नेतृत्व वाली सरकार।
संरचनात्मक चुनौतियाँ:
• दक्षिण एशिया में बीजिंग का बढ़ता प्रभाव।
• बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) के माध्यम से चीन की गहरी पकड़ और पहुंच।
• क्षेत्रीय पक्ष हासिल करने के लिए सीमा विवादों को निपटाने की चीन की रणनीति।
II. भूराजनीतिक बफर:
• दक्षिण एशिया में संयुक्त राज्य अमेरिका की घटती उपस्थिति।
• चीन का आक्रामक उदय एक भू-राजनीतिक बफर के रूप में कार्य करता है, जो भारत के प्रभाव को प्रभावित करता है।
तृतीय· दुविधाओं के कारण:
क्षेत्रीय भूराजनीतिक वास्तुकला:
• अमेरिका के प्रस्थान के साथ बदलती गतिशीलता
• एक अनिवासी शक्ति के रूप में चीन का उदय।
नीति रुख:
• क्षेत्रीय राजनीति से निपटने में यथास्थिति पूर्वाग्रह।
• सत्ता में बैठे लोगों के साथ जुड़ने पर अत्यधिक निर्भरता, अलगाव की ओर ले जाती है।
III .ग़लत धारणाएँ:
• विश्वास है कि पाकिस्तान को छोड़कर दक्षिण एशिया भारतीय भू-राजनीतिक हितों के अनुरूप होगा।
• यह धारणा कि भारत के सांस्कृतिक संबंध चीन के दृष्टिकोण से अधिक लाभप्रद होंगे।

IV. **कार्रवाई के लिए सिफ़ारिशें:**
मौलिक परिवर्तनों को अपनाएँ:
• दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन में मूलभूत बदलाव को स्वीकार करें।
• चीन को क्षेत्रीय प्रधानता के गंभीर दावेदार के रूप में पहचानें।
बाहरी अभिनेताओं की भागीदारी:
• चीन के प्रभाव को संतुलित करने के लिए मित्रवत बाहरी अभिनेताओं को सक्रिय रूप से शामिल करें।
लचीली कूटनीति:
• पड़ोसी देशों के भीतर कई अभिनेताओं के साथ जुड़ें।
• भारत विरोधी तत्वों को खारिज करने के बजाय भारत विरोधी भावना को कम करने पर ध्यान दें।
राजनयिक संसाधन बढ़ाएँ:
• राजनयिकों की कमी को एक महत्वपूर्ण चुनौती के रूप में पहचानें।
• विदेश नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए अधिक कर्मियों की आवश्यकता का समाधान करना।

No fait accompli

1. राजनीतिक समयरेखा:
• निर्वाचित सरकार का पतन, राज्यपाल शासन लागू होना और उसके बाद नाटकीय परिवर्तन।
• विशेष दर्जा प्रदान करने वाले अनुच्छेद 370 को हटाना, जिससे केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजन हो गया।
2. हालिया विधान:
• लोकसभा ने दो विधेयक पारित किए: जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2023, और जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023।
• प्रस्तावित बदलावों से विधानसभा सीटों की संख्या 107 से बढ़कर 114 हो गई है, जिसमें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें शामिल हैं।
• यूटी द्वारा घोषित "अन्य पिछड़ा वर्ग" के साथ संरेखित करने के लिए जम्मू-कश्मीर आरक्षण अधिनियम, 2004 में शब्दावली का प्रतिस्थापन।

3. **चिंताएँ बढ़ीं:**

• संवैधानिक संशोधनों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक विधायी बदलावों के औचित्य पर सवाल उठाना।

• जम्मू-कश्मीर के निर्वाचित प्रतिनिधियों की भागीदारी का अभाव, परिवर्तनों को नागरिकों के लिए नियति के रूप में प्रस्तुत करना।

• हाइलाइटिंग मुद्दे: पिछले 5.5 वर्षों में राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रता का निलंबन, गिरफ्तारियां, संचार शटडाउन, मीडिया प्रतिबंध और बिजली कटौती।

4. **लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को बहाल करने का आह्वान:**

• लोकप्रिय चुनावों के माध्यम से लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को बहाल करने और राज्य का दर्जा बहाल करने पर जोर।

• अलगाववाद और आतंकवाद की क्षेत्रीय चुनौतियों के बीच नागरिक अलगाव को संबोधित करने और नागरिक जुड़ाव को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष:

• जम्मू-कश्मीर में तत्काल रिक्तियों को दूर करने और क्षेत्रीय अस्थिरता में योगदान देने वाले लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों को हल करने की दिशा में काम करने के लिए लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और राज्य का दर्जा बहाल करने की तत्काल आवश्यकता है।

भारत में डीपफेक और एआई को विनियमित करना

डीपफेक तकनीक:

• परिभाषा: डीपफेक वीडियो, ऑडियो रिकॉर्डिंग या छवियों सहित डिजिटल मीडिया में हेरफेर करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) एल्गोरिदम का उपयोग करते हैं। मशीन लर्निंग का लाभ उठाकर, डीपफेक तकनीक अति-यथार्थवादी परिवर्तन उत्पन्न करती है जो वास्तविकता और कल्पना के बीच की रेखा को धुंधला कर देती है।

• **प्रभावशाली हेरफेर:** विशेष रूप से, रश्मिका मंदाना के एक वायरल वीडियो में डीपफेक तकनीक का उपयोग किया गया है, जिससे प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने, सबूत गढ़ने और लोकतांत्रिक संस्थानों में विश्वास कम करने की क्षमता के कारण व्यापक चिंता पैदा हो गई है।

• **राजनीतिक क्षेत्र:** राजनीतिक अभियानों में डीपफेक का इस्तेमाल किया गया है, जैसा कि भाजपा के मनोज तिवारी और एमपी कांग्रेस प्रमुख कमल नाथ जैसे राजनेताओं को दर्शाने वाले वीडियो के प्रसार में देखा गया है, जो राजनीतिक आख्यानों में हेरफेर पर चिंता पैदा करते हैं।

• **वैश्विक प्रभाव:** इस तकनीक ने अंतरराष्ट्रीय घटनाओं को प्रभावित किया है, यह अर्जेंटीना के राष्ट्रपति चुनावों में इसके उपयोग और कथित तौर पर यूक्रेनी राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की को चित्रित करने वाले एक डीपफेक वीडियो के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है, जो इसके व्यापक वैश्विक निहितार्थों को उजागर करता है।

डीपफेक का लिंग आधारित प्रभाव:

• **अनुपातहीन दुरुपयोग:** डीपफेक, मुख्य रूप से अश्लील सामग्री पर केंद्रित है, मुख्य रूप से महिलाओं को लक्षित करता है, चौंकाने वाले आंकड़ों से संकेत मिलता है कि इन हेरफेर किए गए वीडियो में से एक महत्वपूर्ण बहुमत (96%) में महिलाएं (99%) शामिल हैं।

• **प्रौद्योगिकी का हथियारीकरण:** अपमानजनक साझेदारों ने उन महिलाओं को शर्मिंदा करने के लिए डीपफेक तकनीक का इस्तेमाल किया है जो आगे बढ़ने से इनकार करती हैं, मनोवैज्ञानिक आघात पहुंचाती हैं और पीड़ितों को सामाजिक कलंक का शिकार बनाती हैं।

कानूनी ढांचा और प्रस्तावित सुधार:

• **वर्तमान कानूनी परिदृश्य:** आईटी अधिनियम और आईपीसी के तहत धाराओं सहित मौजूदा कानून, डीपफेक-संबंधित अपराधों को संबोधित करने का प्रयास करते हैं। हालाँकि, निवारक उपायों में खामियाँ मौजूद हैं, और ये कानून विशेष रूप से डीपफेक जैसी उभरती एआई-संचालित प्रौद्योगिकियों से निपटने के लिए डिज़ाइन नहीं किए गए थे।

• **चुनौतियाँ और प्रतिक्रियाएँ:** वर्तमान कानून पीड़ितों पर शिकायत दर्ज करने का दायित्व डालता है, जबकि जेनरेटिव एआई तकनीक के बारे में व्यापक समझ की कमी प्रभावी कानूनी कार्रवाई में बाधा डालती है।

• **सरकारी पहल**: सरकारी प्रस्तावों में डीपफेक निर्माण और लेबलिंग के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नियमों का मसौदा तैयार करना शामिल है, जिसमें रचनाकारों और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों दोनों की जिम्मेदारी पर जोर दिया गया है। मौजूदा कानूनों की पर्याप्तता पर राय अलग-अलग है।

न्यायिक परिप्रेक्ष्य और अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण:

• **न्यायिक दृष्टिकोण:** दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्देश जारी करने के बारे में आपत्ति व्यक्त की है, जिसमें सुझाव दिया गया है कि सरकार संतुलित तरीके से डीपफेक-संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित हो सकती है।

• **वैश्विक प्रयास:** अमेरिका, चीन और यूरोपीय संघ जैसे देश डीपफेक से निपटने के लिए विभिन्न नियमों को अपनाते हैं, जिसमें दुरुपयोग के लिए लेबलिंग, ट्रेसिंग और दंड लगाने जैसे उपायों पर जोर दिया जाता है।

भविष्य की रणनीतिः

• **व्यापक दृष्टिकोणः** शासन को केवल कानूनी संशोधनों से आगे बढ़ना चाहिए, जिसमें सुरक्षा मानकों की स्थापना, जागरूकता बढ़ाना और डीपफेक जैसी एआई प्रौद्योगिकियों द्वारा उत्पन्न चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए संस्थान निर्माण शामिल होना चाहिए।

• **भारतीय संदर्भः** भारत की विकासशील अर्थव्यवस्था और संपन्न स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को ध्यान में रखते हुए, नवाचार और विनियमन के बीच संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है, यह सुनिश्चित करना कि विधायी प्रतिक्रियाएं प्रगति को बाधित किए बिना तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देती हैं।

• **नवोन्मेषी नीति संबंधी विचारः** सुझावों में एआई के लिए नियामक सैंडबॉक्स जैसे नवोन्मेषी नीति टूल की खोज करना, अन्य क्षेत्रों से सीखना और एआई प्रौद्योगिकी को विनियमित करने की आड़ में मुक्त भाषण को कम करने से बचना शामिल है।

नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने की सीमा

वैश्विक परिदृश्य:

• IEA का तत्काल आह्वान: IEA ने वैश्विक स्तर पर देशों से 2030 तक नवीकरणीय क्षमता को तीन गुना करने का आग्रह किया है, दुबई में COP28 में 118 देशों ने समर्थन देने का वादा किया है, फिर भी भारत, चीन, रूस और सऊदी अरब जैसे प्रमुख खिलाड़ी शामिल नहीं हुए हैं।

• **अनुमान**: IEA का अनुमान है कि 2050 तक नवीकरणीय ऊर्जा वैश्विक बिजली उत्पादन में 80% तक बढ़ जाएगी, जबकि कोयले का योगदान घटकर 3% हो जाएगा। प्राथमिक स्रोतों में जलविद्युत (16.1%), पवन (5.6%), और सौर (3.8%) शामिल हैं।

नवीकरणीय स्रोतों में चुनौतियाँ:

जलविद्युत ऊर्जा:

• **बाधाएँ**: पर्यावरणीय चिंताओं, उपयुक्त जल निकायों की आवश्यकता, नियामक बाधाओं और वकालत समूहों के विरोध के कारण बड़े बाँधों के निर्माण में चुनौतियाँ।

• **व्यवहार्यता**: 2030 तक जलविद्युत क्षमता को तीन गुना करना असंभव लगता है, जो नवीकरणीय ऊर्जा का 57% है।

सौर एवं पवन ऊर्जा:

• **विकास की आवश्यकता:** 2030 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए, सौर और पवन ऊर्जा उत्पादन में कम से कम पांच गुना वृद्धि होनी चाहिए।

चिंताएँ: दिन के उजाले पर निर्भरता, भूमि उपयोग संघर्ष, पर्यावरणीय प्रभाव और आयात पर निर्भरता के कारण सौर ऊर्जा को सीमाओं का सामना करना पड़ता है। पवन ऊर्जा की दक्षता मौसम पर निर्भर है, और टरबाइन उत्पादन महत्वपूर्ण उत्सर्जन उत्पन्न करता है।

जीवाश्म ईंधन और नवीकरणीय संतुलन:

• **प्रतिज्ञा अस्पष्टता**: नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने पर COP28 के फोकस में समग्र जीवाश्म ईंधन निर्भरता को कम करने पर स्पष्टता का अभाव है, जो संभवतः अमेरिका जैसे देशों को ऊर्जा उत्पादन का 80% होने के बावजूद जीवाश्म ईंधन उत्पादन बढ़ाने की अनुमति देता है।

प्रौद्योगिकी और वित्तीय बाधाएँ:

• तकनीकी सीमाएँ: सौर और पवन ऊर्जा के लिए रुक-रुक कर होने वाली चुनौतियाँ बैकअप स्रोतों या महंगे ऊर्जा भंडारण समाधानों की माँग करती हैं, जिससे विश्वसनीयता और लागत प्रभावित होती है।

• वैश्विक निवेश: नवीकरणीय ऊर्जा में परिवर्तन के लिए पर्याप्त निवेश की आवश्यकता होती है, जिससे विशेष रूप से कम समृद्ध देशों पर वित्तीय दबाव पड़ता है।

भारत की प्रगति और आर्थिक चुनौतियाँ:

• नवीकरणीय प्रगति: भारत ने अपनी नवीकरणीय क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि की है, फिर भी ऊर्जा परिवर्तन में चल रहे प्रयासों के बावजूद, बजट की बाधाएं तेजी से बदलाव में बाधा बन रही हैं।

वैश्विक अनिवार्यताएँ:

• अनदेखी वास्तविकताएँ: कम समृद्ध देशों में चर्चाएँ अक्सर तकनीकी सीमाओं, वित्तीय सहायता आवश्यकताओं, आयात निर्भरता और वित्तीय बाधाओं को दरकिनार कर देती हैं।

• संक्रमण जटिलता: सघन ऊर्जा स्रोतों से कम संकेंद्रित नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में बदलाव तकनीकी और धन सृजन की चुनौतियाँ पैदा करता है, जिसके लिए अप्रमाणित या अभी तक आविष्कार न की गई प्रौद्योगिकियों की आवश्यकता होती है।

निष्कर्ष:

नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ाने के वैश्विक प्रयासों के बीच, तकनीकी चुनौतियों, वित्तीय सहायता और नवीन समाधानों को संबोधित करने के लिए एक व्यावहारिक दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। इन चुनौतियों को संतुलित करने से उत्सर्जन में पर्याप्त कमी और टिकाऊ ऊर्जा भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा।

Mining for critical minerals: what is the auction process, why is it important?

परिचय:

• **बोली जारी**: बैटरी और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए महत्वपूर्ण लिथियम अयस्क सहित 20 महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों की नीलामी 29 नवंबर को शुरू हुई, जिसका उद्देश्य आयात में कटौती और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है।

• **खनिज और उपयोग**: इन ब्लॉकों में निकल, तांबा, मोलिब्डेनम जैसे आवश्यक खनिज और वाहन बैटरी, ऊर्जा भंडारण, इलेक्ट्रॉनिक्स और उद्योगों में महत्वपूर्ण दुर्लभ पृथ्वी तत्व शामिल हैं।

भौगोलिक वितरण और अधिकार नीलाम:

• **ब्लॉक वितरण:** विभिन्न खनिज भंडार वाले आठ राज्यों में फैला हुआ: तमिलनाडु (7 ब्लॉक), ओडिशा (4), बिहार (3), उत्तर प्रदेश (2), और गुजरात, झारखंड, छत्तीसगढ़ और जम्मू और कश्मीर में एक-एक .

• **खनन लाइसेंस (एमएल) और समग्र लाइसेंस (सीएल)**: एमएल (खनन अधिकार) के लिए तत्काल संचालन की अनुमति देने वाले 4 ब्लॉकों की नीलामी की गई; एमएल रूपांतरण की मांग से पहले भूवैज्ञानिक अन्वेषण को सक्षम करने के लिए सीएल के लिए शेष 16 ब्लॉक।

मंजूरी और पूर्व-संचालन आवश्यकताएँ:

• भूमि की स्थिति: रियायती क्षेत्र का लगभग 17% (1,234 हेक्टेयर) वन भूमि की स्थिति के अंतर्गत आता है।

• **प्री-ऑपरेशन मंजूरी:** संचालन शुरू करने से पहले 15 मंजूरी की आवश्यकता होती है, जिसमें वन और पर्यावरण मंजूरी, ग्राम सभा की सहमति आदि शामिल है।

प्रमुख खनिजों में अनुमानित भंडार:

• **लिथियम**: जम्मू-कश्मीर और छत्तीसगढ़ में सीएल के लिए 2 ब्लॉक; जम्मू-कश्मीर ब्लॉक में बॉक्साइट के अनुमानित भंडार का अनुमान है जिसमें 3,400 टन लिथियम धातु और 70,000 टन टाइटेनियम धातु है।

• **निकल और तांबा:** बिहार, गुजरात और ओडिशा में निकेल अयस्क के भंडार पाए गए; ओडिशा ब्लॉक अन्य धातुओं के अलावा 2.05 मिलियन टन निकल अयस्क और 6.09 मिलियन टन तांबा अयस्क प्रदान करता है।

वर्तमान आयात और निर्भरता:

• **आयात सांख्यिकी:** आयात पर भारत की निर्भरता: लिथियम के लिए 100%, निकल के लिए 100%, और तांबे के लिए 93%।

• **FY23 आयात लागत:** 2,145 टन लिथियम कार्बोनेट और ऑक्साइड, 32,000 टन कच्चा निकल और 1.2 मिलियन टन तांबा अयस्क का आयात किया गया।

नीलामी के बाद और भविष्य की संभावनाएँ:

• **नीलामी परिणाम:** उच्चतम खनिज प्रेषण मूल्य के आधार पर नीलामी; इस दौर के बाद नीलामी की दूसरी किश्त अपेक्षित है।

• **आगामी अन्वेषण:** भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण महत्वपूर्ण खनिजों के लिए 125 परियोजनाओं में शामिल है; समिति महत्वपूर्ण खनिजों के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की सिफारिश करती है।

निष्कर्ष:

चल रही नीलामी संसाधन स्वतंत्रता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतीक है, जिसका लक्ष्य आयात निर्भरता को कम करना और घरेलू खनिज निष्कर्षण को बढ़ावा देना है, जो भारत के विकास, आत्मनिर्भरता और आवश्यक खनिजों पर रणनीतिक नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण है।

प्रीलिम्स बूस्टर

प्रधानमंत्री आज लाल किले में प्रथम भारतीय कला, वास्तुकला और डिजाइन द्विवार्षिक का शुभारंभ करेंगे

📌 पहला भारतीय कला, वास्तुकला और डिजाइन द्विवार्षिक (आईएएडीबी) संस्कृति मंत्रालय के नेतृत्व में लॉन्च होने के लिए तैयार है और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के लाल किले में करेंगे।

📌 IAADB का लक्ष्य वेनिस, साओ पाउलो और दुबई में प्रसिद्ध पहलों के साथ तालमेल बिठाते हुए खुद को एक प्रमुख वैश्विक सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में स्थापित करना है।

📌 IAADB के अलावा, आत्मनिर्भर भारत सेंटर फॉर डिज़ाइन और स्टूडेंट बिएननेल, समुन्नति का भी उद्घाटन लाल किले पर किया जाएगा।

टेलर स्विफ्ट को टाइम का 'पर्सन ऑफ द ईयर' नामित किया गया।

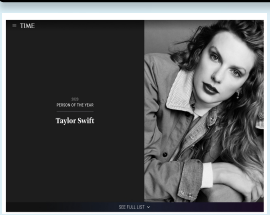

टेलर एलिसन स्विफ्ट एक अमेरिकी गायक-गीतकार हैं। उन्हें उनकी गीत लेखन, संगीत की बहुमुखी प्रतिभा, कलात्मक पुनर्निर्माण और लोकप्रिय संस्कृति और संगीत उद्योग पर प्रभाव के लिए पहचाना गया है।

संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने गाजा युद्धविराम के लिए दुर्लभ अनुच्छेद का आह्वान किया, जिससे इसराइल नाराज हो गया

📌 संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 99 महासचिव को अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को खतरे में डालने वाले मामलों को सुरक्षा परिषद के ध्यान में लाने का अधिकार देता है।

📌 सुरक्षा परिषद पांच स्थायी सदस्य देशों और दस अस्थायी सदस्यों से बनी है।

📌 अनुच्छेद 99 में महासचिव से राजनीतिक निर्णय, चातुर्य और सत्यनिष्ठा के उच्चतम गुणों का प्रयोग करने की अपेक्षा की गई है।

📌 अनुच्छेद 99 लागू करने के पिछले उदाहरणों में 1960 में कांगो गणराज्य में उथल-पुथल और 1961 में ट्यूनीशिया की मांग शामिल है।

📌 महासचिव गुटेरेस ने इज़राइल और अधिकृत फ़िलिस्तीन क्षेत्र में भयावह मानवीय पीड़ा और विनाश के कारण अनुच्छेद 99 लागू किया।

📌इजरायल का सैन्य अभियान शुरू होने के बाद से 40% बच्चों सहित 15,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं।

📌 यूएई ने तत्काल मानवीय युद्धविराम की मांग करते हुए सुरक्षा परिषद में एक मसौदा प्रस्ताव पेश किया है।

पुतिन-एमबीएस बैठक के बाद रूस, सऊदी ने ओपेक+ शक्तियों से तेल कटौती में शामिल होने का आग्रह किया

सितंबर 2021 तक, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (ओपेक) में 13 सदस्य देश हैं। ये देश हैं:

1. अल्जीरिया
2. अंगोला
3. कांगो
4. इक्वेटोरियल गिनी
5. गैबॉन
6. ईरान
7. इराक
8. कुवैत
9. लीबिया
10. नाइजीरिया
11. सऊदी अरब
12. संयुक्त अरब अमीरात
13. वेनेजुएला

ये सदस्य देश सामूहिक रूप से दुनिया के तेल भंडार और उत्पादन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रखते हैं।

सरकार ने FY23 में ग्रीन बांड के माध्यम से आरई के लिए ₹6,100 करोड़ से अधिक प्रदान किया

💰 **धन उगाही**: सरकार ने पिछले वित्तीय वर्ष में सॉवरेन ग्रीन बांड के माध्यम से ₹16,000 करोड़ जुटाए, जिससे नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए किफायती धन उपलब्ध कराया गया। (💸)

🌿 **नवीकरणीय ऊर्जा के लिए आवंटन:** जुटाई गई कुल राशि में से, ₹6,186 करोड़ विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा पहल का समर्थन करने के लिए आवंटित किए गए थे। यह स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को उजागर करता है। (🌱)

🏢 **सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स क्लब:** भारत सरकार 25 जनवरी, 2023 को 80 बिलियन रुपये (1 बिलियन अमेरिकी डॉलर) की दो-किश्त डील जारी करके सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स क्लब में शामिल हो गई। हरित वित्तपोषण के प्रति सरकार के समर्पण को प्रदर्शित करते हुए, बांड को पांच और दस साल की अवधि के बीच समान रूप से विभाजित किया गया था। (🏛️)

सॉवरेन ग्रीन बांड राष्ट्रीय सरकारों द्वारा विशेष रूप से पर्यावरण अनुकूल परियोजनाओं और पहलों के लिए धन जुटाने के लिए जारी किए गए वित्तीय साधन हैं। ये बांड पारंपरिक सरकारी बांड के समान हैं, लेकिन स्थिरता, जलवायु परिवर्तन शमन और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने वाली परियोजनाओं के वित्तपोषण पर विशेष ध्यान देते हैं।

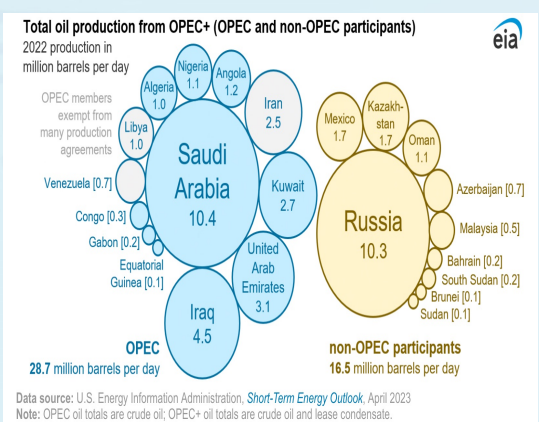

t.me/pragyeshIASMENTOR Pragyesh IAS pragyesh.org